

प्रेषक,

डा० एम० रशीद जोशी,  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,  
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०,  
देहरादून।

कर्जा विभाग,

देहरादून: दिनांक: ७ अप्रैल, 2004

विषय:- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु AREP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 में संलग्न विवरणानुसार (संलग्नक-I, II, III) विभिन्न जनपदों में उनके सम्मुख अकित संख्या में ग्रामों/तोकों का विद्युतीकरण किये जाने हेतु व्यय बहन के लिये प्रथम किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय रु० ६,५१,४२,०००/- (रु० ४ करोड़ इक्षावन लाख ब्यालिस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तों के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। जनपदवार स्वीकृत धनराशि का विवरण संलग्न है। (संलग्नक-IV)

2. उक्त धनराशि AREP योजनान्तर्गत REC से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विभिन्न योजना कोड संख्या के रूप में स्वीकृत कुल ऋण रु० ६५,१४,३४,०००/- के सापेक्ष अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष राज्य सरकार से उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० को REC की सभी शर्तों के प्राविधानानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। REC से प्राप्त ऋण के सम्बन्ध में राज्य शासन, UPCL (लाभार्थी) एवं REC के मध्य हस्ताक्षर किये गये अनुबन्ध एवं हाईपोथिकेशन अनुबन्ध की सभी शर्तों का पालन UPCL द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि AREP योजनान्तर्गत REC से रवैकृत निम्नलिखित ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के सापेक्ष चिह्नित गांवों/तोकों के विद्युतीकरण एवं सम्बन्धित योजना में वर्णित विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यों के व्यय बहन हेतु इस प्रकार किया जायेगा कि रवैकृत योजना में उल्लिखित न्यूनतम समयावधि में विद्युतीकरण एवं वर्णित सभी कार्यों को शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा।

क०सं०	योजना कोड संख्या	कुल ऋण धनराशि	जनपद	ग्रामों की संख्या	तोकों की संख्या
1-	580001 से 580007 तक	4351.57	रुद्रप्रयाग	23	-
			उत्तरकाशी	27	-
			चमोली	89	-
			अल्मोड़ा	37	-
			बागेश्वर	55	-
			चम्पावत	21	-
			पिथौरागढ़	67	-
2-	580008 से 580009 तक	426.65	देहरादून	-	49
			टिहरी	-	42
3-	580010 से 580018 तक	1736.12	पौड़ी	124	-
			टिहरी	83	-
	योग:-	6514.34		526	91

4. उक्त जनपदों के समुख ग्रामों/तोकों की संख्या के सापेक्ष विद्युतीकरण हेतु योजना में चुने गये ग्रामों/तोकों की सूची तत्काल शासन, सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जायेगी तथा सम्बन्धित ग्राम के ग्राम प्रधान को भी सूचित किया जायेगा कि उनके किस गांव/तोक का विद्युतीकरण इस योजना के अधीन कब तक किये जाने का लक्ष्य है, वहां न्यूनतम कितने विद्युत संयोजन किस श्रेणी के दिये जाने हैं एवं क्या-क्या अन्य कार्य सम्मिलित है। सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को भी श्रेणीवार विद्युत संयोजन दिये जाने एवं किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाय।

5. उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा प्रत्येक दशा में REC से सम्बन्धित योजनाओं के लिये ऋण स्वीकृति की सूचना सम्बन्धी REC के पत्रों के संलग्नक A व B (प्रतियां संलग्न) में इगत सभी शर्तों की शत प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। इसमें त्रुटि की दशा में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० एवं उनके सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

6. UPCL द्वारा योजना के अधीन विद्युतीकरण का कार्य समय से पूर्ण कर REC से तत्काल एवं समय से प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत कर सम्पूर्ण योजना के लिये स्वीकृत ऋण के समतुल्य धनराशि की समय से प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी एवं जहां सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, उसे UPCL द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा।

7. ग्रामों/तोकों के विद्युतीकरण/योजना में वर्णित सुविधाओं के सुजन के पश्चात् सम्बन्धित ग्राम प्रधान से नियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर REC व शासन को प्रेषित किया जायेगा, जैसा कि योजना की शर्तों में वर्णित है। साथ ही विद्युतीकरण उपरान्त ग्रामों/तोकों की सूची समयान्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जायेगी, जो अपने रत्त से इसका सत्यापन कर सकेंगे। जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्तानुसार सत्यापन में पाई गई किसी त्रुटि या कमी तथा सत्यापन का विवरण UPCL एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8. REC द्वारा स्वीकृत योजना में सम्बन्धित ग्रामों/तोकों के विद्युतीकरण के साथ-साथ योजना में इगत निर्धारित संख्या में विद्युत संयोजनों/भार की प्राप्ति, जैसा कि संलग्नक-I, II, III में वर्णित है, भी अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

9. नियत अवधि में कार्य पूर्ण न होने पर ब्याज की अतिरिक्त देयता की जिम्मेदारी UPCL/UPCL के सम्बन्धित अधिकारियों की होगी।

10. ऋण एवं ब्याज की समय से बापसी उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा ऋण बापसी के विस्तृत विवरण (साक्ष्यों सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा)। नोरेटोरियम की अवधि में देय ब्याज का समय से भुगतान भी उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं इस सम्बन्ध में भुगतान के विवरण साक्ष्य सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. नियत अवधि पर भुगतान/बापसी न करने पर 2.75 प्रतिशत चकवृद्धि ब्याज दण्ड के रूप में अतिरिक्त देय होगा तथा 6 माह से अधिक भुगतान/बापसी में चूक की दशा में योजना का विशेष रचरूप समाप्त हो जायेगा, जिस दशा में ऋण पर सामान्य ब्याज (ऋण स्वीकृति के समय प्रचलित) लगेगा। अतः उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा प्रत्येक दशा में योजना का संपादन/कियान्वयन निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार समय से करते हुये नियत तिथि तक किश्त व ब्याज की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना में प्रथम किश्त आहरण के बाद यदि कोई प्रतिपूर्ति दावा एक वर्ष की अवधि में REC को प्रत्यक्ष नहीं किया जायेगा तो प्रथम किश्त में अवमुक्त सम्पूर्ण ऋण की राशि को ब्याज/दण्ड ब्याज सहित REC को बापस किया जायेगा।

13. उक्त स्वीकृत राशि पर ब्याज की देयता 29 मार्च, 2004 से आगणित होगी, जिस तिथि को REC से यह राशि अवमुक्त हुई है।

14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित समय में उपयोग कर उस धनराशि से योजनावार कार्य की पित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा, ताकि आगामी किश्त की भारत सरकार से प्राप्त होने में विलम्ब न हो।

15. किरतों एवं ब्याज की वापसी नियत तिथि से पूर्व अवश्य कर दिया जाय एवं इस हेतु नोटिस/सूचना का इत्तजार न किया जाय। धनराशि रीधे REC लो भुगतान करते हुये शासन को सूचना समझ दी जाय।
16. रखीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वीजक पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिंगो के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहरताक्षर उपरान्त कोषागार में प्रस्तुत कर किया जायेगा।
17. रखीकृत की जा रही धनराशि लेखानुदान के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-विजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारेण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों व अन्य उपकर्मों में निवेश-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाये-104-उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लिंगो को REC से ऋण-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं-05/वि०अनु०-३/2004, दिनांक 05 अप्रैल, 2004 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।  
संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

(डा०ए०सी० जोशी)  
अपर सचिव

संख्या: (१५६१/०४) ५५६ / नौ-३-ऊ / RECARREP / ०३, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल।
- 2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मंख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 3- निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा० राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
- 4- जिलाधिकारी, देहरादून/समर्त सम्बन्धित जिलाधिकारी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
- 7- सचिव, नियोजन विभाग।
- 8- वित्त अनुभाग-३।
- 9- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(डा०ए०सी०जोशी)  
अपर सचिव

Rural Electrification Corporation Limited  
(A Government of India Enterprise)

21/02/2008 - A

**Annexure (A)**

**Terms & Condition (GENERAL) applicable to loan for  
P: VE(SG) category**

1. Unless the Corporation otherwise agrees in writing, the loan of the scheme shall be disbursed over a period of one year from the date of award of contract.
2. The loan would be disbursed to the State Govt. which would make the funds available to the executing agency under the terms and conditions as sanctioned by REC.

The State Government/concerned Central Power Utility would undertake to arrange for necessary budget provision in the Annual Budget(s) of the State/concerned State Power Utilities for Prompt repayment of loan to REC and shall also undertake to ensure to arrange payment of monthly installment towards loan repayment together with interest as applicable on requisition from the Corporation before the last date of the month.

Additionally the State Government concerned Central Power Utility shall ensure creation of charge in favour of the Corporation by way of hypothecation of future assets to be created out of the project loan sanctioned by REC Hypothecation of assets will have the same meaning as defined in the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

2. The disbursement procedure shall be as follows:
  - a) Separate bank account has to be opened by borrower for payments - monthly statement and certificate to be furnished to REC
  - b) Each disbursement would be based on utilisation certificate and proof of the payments against the earlier instalment.
  - c) The first instalment up to 10% of the loan amount shall be released on execution of loan documents and compliance of stipulated terms and conditions in the sanction letter.
  - d) The second and subsequent instalment of loan shall be released on reimbursement basis depending upon the progress of works indicated in the claims preferred by the borrower after pro-rata adjustments of initial advance of 1<sup>st</sup> instalment.

it will be dependent on

- e) The final 10% of the loan amount shall be released after final field monitoring and on submission of confirmation letter from Gram Pramukh/Sarpanch indicating name and date of Electrification of New Village/Hamlet/Dalit Bastis and on completion of "defects/correction period" if assigned to the turn key contractor. The deviation, if any, shall be considered at the time of submission of final claim as per REC guidelines.

including status of

- 3. The State Government shall complete the work relating to the scheme within a period of one year from the date of award of contract. The Corporation at its discretion may agree to the request of the State Govt. to extend the period of implementation of the project/scheme.
- 4. The State Government shall submit its application for the loan duly supported by such certificates and authentications in the forms as may be prescribed for the purpose by the Corporation.
- 5. The State Government shall execute such agreements, Hypothecation Deed, and documents as may be prescribed for the purpose by the Corporation.
- 6. The Corporation shall be free and fully empowered not to disburse any further loan, if it is found to its satisfaction that the loan or loans already disbursed have not been properly utilized by the State Govt. or it has committed any default in meeting its obligation and commitments to the Corporation in terms of the provisions of the agreement.
- 7. The loan shall also be subject to such further terms and conditions as may be laid down in the forms of agreement executed or to be executed by the State Government.
- 8. The State Govt. agrees that :

- i) It shall ensure provision of Dalit Bastis in the scheme area have been invariably included for electrification under P:VE(SG) scheme.
- ii) It shall also ensure provision for release of Kutir Jyoti connections to all the households of the rural poor in the villages covered or at least 10 households of the rural poor in each village has been made under P:VE(SG) scheme.
- iii) It shall undertake that whenever a village is declared electrified, the name of village shall be intimated to the MPs, MLAs of the area and Gram Pramukh/Sarpanch of the village and acknowledgement in confirmation of village having been electrified will be obtained from Gram Pramukh/Sarpanch of the village by the Power Deptt. and reported to REC and CEA.

9. It will be open to the Rural Electrification Corporation to depute its officers and staff for the inspection of matters relating to the scheme, to have access to such books and records of the State Govt./Power utility as may be deemed necessary by the inspecting Staff. The State Govt./Power Utility shall also furnish to the Corporation such reports on its working either in general or in specific relation to the project financed by the Corporation from time to time including status of future assets being created out of Projects Loan.

Annexure (D)

10. ~~Terms & Conditions~~ The loan shall also be subject to such further terms and conditions as may be laid down in the form of the Loan Agreement and Hypothecation Deed to be executed by the State Govt. and the executing agency.

11. 1. The State Government shall have to certify that:

- No provision has been made in the State Plan outlays for financing of the scheme.
- If the scheme is fully and adequately funded by the State Government, it will not, for meeting any part of the capital outlay for the works included in which the scheme, raise borrowings from other sources such as LIC or Commercial Banks,
- If the scheme is partially funded by the State Government, it will do so only after obtaining the permission of the Corporation and
- The scheme has been formulated on the latest cost data approved by the Corporation.

2. Notwithstanding anything stated hereinbefore it will be open to the Corporation to periodically, reduce or enhance the rate of interest in respect of the loan instalments not disbursed up to the date of such revision in the rate of interest. The revision in the rate of interest shall take effect from such date as may be notified by the Corporation in this behalf.

3. Consultant may be appointed by the State Govts., at their discretion to assist them in formulation of project, bidding documents, evaluation of award of contract and monitoring of progress of work. The Consultant so appointed shall also be responsible for reporting monthly progress of work to the Ministry of Power, Central Electricity Authority and Rural Electrification Corporation through their respective State Govts. In accordance with the scheme stipulations.

**RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION LIMITED**  
**( A Government of India Enterprise)**

The period of moratorium for repayment of loan will be 15<sup>th</sup> day of the month of disbursement of first instalment of loan from the date of disbursement of the first instalment of loan.

**Annexure (B)** by the State Govt. within a period of one year from the date of disbursement of the first instalment of loan.

**Terms & Condition applicable to loan for**

P: VE(SG) category shall pay Interest on the loan during the period of moratorium. The repayment period will be 15 years on the basis of

1. The State Government shall pay Interest on the loan at 3% per annum for the entire period of 13 years from the date of disbursement of the first instalment of loan. Interest will be charged quarterly till the end of the repayment period.
2. If the scheme is fully and successfully implemented as sanctioned, the interest to be charged and received as above will be considered for waiver by REC and refunded to the Borrower, or adjusted against repayment of principal loan amount, which would make the scheme actually interest free. The concerned states of these schemes shall be withdrawn and the concerned state government shall be relieved of any liability on this scheme.
3. If the scheme is not fully and successfully implemented within the period of one year from the date of disbursement of first instalment of loan and on award of turn-key contract, or within the extended period for implementation of the project/scheme beyond the period of one year as may be agreed to by REC at its discretion under special circumstances on the merits of each case, at the specific request of the State Govt./Borrower, then the concessional/nominal interest rate as applicable on the above special scheme for Village/Hamlet Electrification and Dalit Bastis Electrification would continue to be payable during the entire period of loan as notified above in para 1.
4. Waiver of the interest shall be considered by REC, only if scheme is successfully and fully completed as per schedule. The completion of scheme shall be considered successful on the basis of the fulfilment of the following:

  - i) The scheme is executed on turn-key basis if not envisaged to be executed departmentally.
  - ii) The scheme is completed within the time-frame as provided in the sanction letter.
  - iii) The scheme has achieved the desired goal i.e. electrification of all such Villages/Hamlets/Dalit Bastis as envisaged in the scheme to be supported by the list of such Villages/Hamlets/Dalit Bastis (Village-wise).
  - iv) Additional expenditure, beyond the loan amount sanctioned by REC under the scheme, if required to complete the electrification of all the Dalit Bastis covered in the scheme, will have to be borne by the State Government from their own funds.

5.50 The period of moratorium for repayment of principal shall be three years from the 15<sup>th</sup> day of the month of disbursement of first instalment of loan but the entire loan shall be repaid by the State Govt. within a period of 13 years (including three years moratorium) from the date of disbursement of the first instalment of loan.

6.10 The State Govt. shall pay interest as indicated in clause(1) above during the period of moratorium. The repayment of principal thereafter will be effected on the basis of equal annual instalments and Interest shall be calculated at the rates prescribed In clause(1) above on the amount outstanding.

7. In the event of any instalment of interest or of principal not being paid to the Corporation by the State Govt. on the due dates, as indicated In clause (1) and (5) above, the State Govt. shall pay to the Corporation a penal rate of compound interest @ 2.75% p.a. above and in addition to the rates of interest stated in clause (1) above. However, if the default persists for more than six months, the special status of the schemes shall be withdrawn and the loan shall stand reverted to normal scheme rate of interest i.e. the base rates prevailing at the time of sanction of scheme, which at present is 9% p.a.

8. Total interest charged shall be adjusted against the last instalment of repayment. No interest is payable to the borrower on the amount of interest refundable.

9. The State Govt. shall also pay levy of interest tax at the prevalent rate per annum as notified by Govt. of India or as may be modified from time to time on the gross interest earnings per annum on this scheme.

10. The Corporation may agree at the request of the State Govt. to extend the period of disbursement of loan and implementation of the project/scheme by one year which will be in addition to the original period for implementation of the scheme. However, the period of moratorium on repayment of loan will continue to remain the same as indicated in clause 5 above and will not be effected by the extension in the period of disbursement of loans and implementation of the project.

11. In the event of the loan documents for drawal of the amount for the first phase duly completed in all respects not being submitted within 6 months from the date of letter conveying sanction of the loan or such further extended period as may be allowed by the Corporation In Its absolute discretion the sanction of the loan shall stand withdrawn.

12. In the event of drawal of only first instalment and no further claim has been received by REC for work done if any even though the period of one year after release of first Instalment of loan has lapsed, the entire loan of 1<sup>st</sup> instalment will be repaid back to REC alongwith interest/penal interest till the date of payment.

KOONA -  
MANJURAS-D

LICENSING OF ALL PROPOSED UNDERGROUND SITES FOR CONSTRUCTION OF THE INTEGRATED CO-OP. LINE

STATE: UTTARANCHAL

Sl. No.	Name of the District or District Division	No. of Regn villages in the districts/ Division	SERVICES PROPOSED				Bursting Rate hrs	Total K.W.	Construction Period hrs	Proposed Date, E.O.D	
			LT Induced no. K.W.	Domestic no. K.W.	Commercial no. K.W.	Residential no. K.W.					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	14	16
1	Baddi & other 22	23	11	41	1378	1376	91	182	0	0	1478
2	Tini & other 26 Birbidihi distt.	27	16	60	1436	1436	58	112	0	0	1508
3	Kheo & other 68 villages in Ghoomod distt.	69	2	6	2063	2263	127	264	0	0	2162
4	Uttarkashi & other 23 villages in Almora distt.	37	13	49	707	707	38	73	0	0	758
5	Darchi & other 54 villages in Dausa & other distt.	55	23	64	1729	1729	140	280	0	0	1864
6	Ganuk & other 20 villages in Chamba & other distt.	21	3	34	479	476	15	33	0	0	522
7	Jissa & other 66 villages in Pauri Garhwal distt.	67	125	511	1837	1837	174	348	0	0	2177
	Total	318	212	757	5557	5557	651	1282	0	0	10640
											11751215015 378101

Scheme code 500001 - 500007

## SANCTION PARAMETERS PROPOSED UNDER PHE(SG) SCHEMES FOR CONSIDERATION OF THE SCREENING COMMITTEE

## STATE: UTTARANCHAL

Sl. No.	Name of the scheme/ District	No. of Virgin Hamlets for electri- fication	S E R V I C E S			P R O P O S E D			Construction works proposed							
			LT Industrial No	Industrial KW	Domestic No	KW	Commercial No	KW	Street light No	KW	Total No	KW	HT Line Km.	L T line Km.	No J capacity kVA	Distr. S/S
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19
1	Chakrata and 3 other blocks in Dehradun distt.	49	0	0	740	740	36	72	0	0	776	812	26	35	31/25 18/16	1063
2	Jaunpur and 8 other blocks in Tehri distt.	42	0	0	678	678	31	62	0	0	709	740	32	58	18/25 30/16	930
Total:		91	0	0	1418	1418	67	134	0	0	1485	1552	58	93	-	-

Scheme code SG 58008 and SG 009

## SANCTION PARAMETERS PROPOSED UNDER PIVE(SO) SCHEMES FOR CONSIDERATION OF THE SCREENING COMMITTEE

STATE: UTTARANCHAL

Sl. No.	Name of the scheme/ District	No. of Villages for electric connection	SERVICES PROPOSED										Construction works proposed			
			LT Industrial		Domestic		Commercial		Street light		Total		HT line Km.	LT line Km.	Distr. S/S capacitly KVA	
1	2	3	4	No.	KW	No.	KW	No.	KW	No.	KW	15	16	17	18	19
1	Rikhanikhali and Nainital blocks in Pauri distt.	25	0	0	410	410	18	30	0	0	428	446	38.00	40.00	9/25 16/16	481
2	Jahankhal block in Pauri distt.	27	0	0	445	445	27	54	0	0	472	499	40.00	40.00	2/25 25/16	450
3	Kaligukhal and 5 other blocks in Pauri distt.	14	0	0	78	78	0	0	0	0	78	78	10.00	15.00	14/16	224
4	Yamkeshwar block in Pauri distt.	19	0	0	350	350	24	48	0	0	374	398	35.00	30.00	4/25 16/16	340
5	Thalisain & Veeranikhali blocks in Pauri distt.	13	0	0	180	180	10	20	0	0	200	210	30.00	30.00	5/25 8/16	253
6	Chamba and 4 other blocks in Tehri distt.	35	0	0	568	568	23	48	0	0	581	604	36.00	50.00	1/83 11/25 21/16	674
7	Jaunpur & Narendranagar blocks in Tehri distt.	21	0	0	338	338	19	38	0	0	357	370	26.00	54.00	11/25 10/16	435
8	Shringar block in Tehri distt.	27	0	0	668	668	26	56	0	0	596	624	44.00	35.00	18/25 8/83	584
9	Duggada & Dhangu blocks in Pauri distt.	28	0	0	450	450	28	56	0	0	478	506	50.00	46.00	4/25 22/16	452
	Total:	207	0	0	3387	3387	177	354	0	0	3564	3741				

Scheme code 500010 to 500010 ✓

## RELEASE ADVICE

State Name : UTTARANCHAL STATE GOVT.

Particulars:

Voucher No : 1

Dated : 29/03/2004

Nature Of Transaction : Cash

Sl. No.	District Name	Check No.	Scheme Code	Category	Instt No.	Released Amnt
1	RUDRAPRAYAG		58000100	P:VE (SG)		3111000.00
2	UTTARKASHI		58000200	P:VE (SG)		7146000.00
3	CHAMOLI		58000300	P:VE (SG)		9882000.00
4	ALMORA		58000400	P:VE (SG)		3913000.00
5	BAGESHWAR		58000500	P:VE (SG)		8314000.00
6	CHAMPAWAT		58000600	P:VE (SG)		2278000.00
7	PITHORAGARH		58000700	P:VE (SG)		8067000.00
8	DEHRADUN		58000800	P:HE (SG)		1905000.00
9	TEHRI		58000900	P:HE (SG)		2361000.00
10	PAURI		58001000	P:VE (SG)		2115000.00
11	PAURI		58001100	P:VE (SG)		1959000.00
12	PAURI		58001200	P:VE (SG)		595000.00
13	PAURI		58001300	P:VE (SG)		2075000.00
14	PAURI		58001400	P:VE (SG)		1578000.00
15	TEHRI		58001500	P:VE (SG)		2326000.00
16	TEHRI		58001600	P:VE (SG)		1931000.00
17	TEHRI		58001700	P:VE (SG)		2335000.00
18	PAURI		58001800	P:VE (SG)		2396000.00

Page Total : 65142000.00

Cumulative Total : 65142000.00